Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

142-2022/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, AUGUST 8, 2022 (SRAVANA 17, 1944 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 8th August, 2022

No. 21-HLA of 2022/68/15987.— The Haryana Water Resources (Conservation, Regulation and Management) Authority (Second Amendment) Bill, 2022 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:-

Bill No. 21-HLA of 2022

THE HARYANA WATER RESOURCES (CONSERVATION, REGULATION AND MANAGEMENT) AUTHORITY (SECOND AMENDMENT) BILL, 2022

A

BILL

further to amend the Haryana Water Resources (Conservation, Regulation and Management) Authority Act, 2020.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Haryana Water Resources (Conservation, Regulation and Management) Authority (Second Amendment) Act, 2022.

Substitution of section 18 of Haryana Act 29 of 2020.

2. For section 18 of the Haryana Water Resources (Conservation, Regulation and Management) Authority Act, 2020, the following section shall be substituted, namely:-

"18. Tariff for bulk and treated waste water.- The Authority shall decide tariff for bulk water uses of surface water and of treated waste water on the principles of economy, efficiency, equity and sustainability. The tariff shall be based on volumetric measurements of water consumption and shall be designed reasonably.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

I. The issue of determination of retail water tariff was deliberated in detail and it emerged that there are a number of departments/corporations/agencies involved in the determination of water tariff to different type of users. Therefore, it would be appropriate to retain the erstwhile prevailing practise of determining the rates of tariff of retail water.

II The Bill proposes to amend the Haryana Water Resources (Conservation, Regulation and Management) Authority Act, 2020 as amended up-to-date and to omit the following provision of sub-section 2 of Section 18 of the Act:

(2) The Authority shall recommend to the Government retail rates of water for individual household, industry or commercial establishment, supplied by concerned entity.".

III The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

MANOHAR LAL,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 8th August, 2022.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2022 का विधेयक संख्या 21–एच0एल0ए0

हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन तथा प्रबन्धन) प्राधिकरण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022

हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन तथा प्रबन्धन) प्राधिकरण अधिनियम, 2020 को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन तथा प्रबन्धन) प्राधिकरण (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2022, कहा जा सकता है।

2020 के हरियाणा अधिनियम 29 की धारा 18 का प्रतिस्थापन।

2. हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन तथा प्रबन्धन) प्राधिकरण अधिनियम, 2020 की धारा 18 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"18. बल्क तथा संसाधित अपजल हेतु टैरिफ.– प्राधिकरण मितव्ययता, क्षमता, निष्पक्षता तथा स्थिरता के सिद्धांतों पर सतही जल तथा संसाधित अपजल के बल्क जल उपयोग के लिए टैरिफ नियत करेगा। टैरिफ, जल की खपत के अनुमापी मापन पर आधारित होगा और उचित रूप से डिजाईन किया जाएगा।"।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

I. खुदरा जल शुल्क के निर्धारण के मुद्दे पर विस्तार से विचार किया गया और यह सामने आया कि उपयोगकर्ताओं के लिए जल शुल्क के निर्धारण में कई विभाग/निगम/एजेंसियां शामिल हैं। इसलिए, खुदरा जल के शुल्क की दरें निर्धारित करने की पूर्ववर्ती प्रचलित प्रथा को बनाए रखना उचित होगा।

II. विधेयक में हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन और प्रबंधन) प्राधिकरण अधिनियम, 2020, अब तक संशोधित में संशोधन करने और अधिनियम की धारा 18 की उप–धारा 2 के निम्नलिखित प्रावधान को हटाने का प्रस्ताव है :–

"(2) प्राधिकरण सरकार को संबंधित इकाई द्वारा आपूर्ति किए गए व्यक्तिगत घर, उद्योग या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के लिए जल की खुदरा दरों की सिफारिश करेगा"

III. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है।

मनोहर लाल,
मुख्यमंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 8 अगस्त, 2022.

आर० के० नांदल,
सचिव।

9811—H.V.S.—H.G.P., Pkl.